एसबीआई ने ग्रीन मैराथन का दूसरा संस्करण शुरू किया

भोपाल, 14 जनवरी (ए)। देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपने वार्षिक फ्लैगशिप प्रोग्राम 'एसबीआई ग्रीन मैराथन' का दूसरा संस्करण आज शुरू किया। सी. वेंकट नागेश्वर, डीएमडी , एसबीआई और राजेश कुमार, सीजीएम, भोपाल सर्किल ने भोपाल ने झंडी दिखाकर मैराथन शुरू किया। इस मैराथन में भोपाल के लगभग 3000 उत्साही धावकों ने हिस्सा लिया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा और सुबेदार गुरप्रीत सिंह, भारतीय स्पोर्ट्स शूटर और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी इवेंट के दौरान मौजूद रहे। रविवार के सुबह तात्या टोपे स्टेडियम में शहर भर के प्रतिभागियों ने 5, 10, 21 किमी. के मैराथन में हिस्सा लिया और हरित भविष्य की शपथ ली। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ''रन फॉर ग्रीन'' थीम में योगदान दिया और अन्य प्रतिभागियों के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। सभी धावकों को ऑर्गेनिक टी-शर्ट्स दिये गये, ताकि स्वच्छ एवं हरे-भरे शहर को बढ़ावा दिया जा सके। मैराथन के बाद उन्हें वृक्षारोपण हेतु बीज दिये गये। एसबीआई अगले 2 महीनों में अपने ग्रीन मैराथन को चेन्नई, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पटना और जयपुर में आयोजित करेगा, जबकि नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरू, त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी में पिछले तीन महीनों में सात मैराथन इवेंट्स आयोजित किये जा चुके हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई ग्रीन मैराथन का हेल्थ पार्टनर है, जबकि एसबीआई लाईफ एसबीआई म्युचुअल फंड्स और एसबीआई कार्ड भी इस शून्य उत्सर्जन इवेंट में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं।

थोक महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत, दिसंबर में 3.80 प्रतिशत रहा डब्ल्यूपीआई

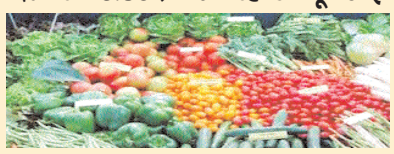

नई दिल्ली, 14 जनवरी (ए)। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर दिसंबर महीने में नवंबर महीने के मुकाबले नरम रही है। दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर 3.80 फीसदी रही है। दिसंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की महंगाई दर 3.59 फीसदी और खाद्य महंगाई दर मासिक आधार पर (-)0.07 फीसदी रही है। इसके अलावा फ्यूल महंगाई दर 8.38 फीसदी रही है जबकि पिछले महीने मासिक आधार पर यह 16.2 फीसदी रही थी। गौरतलब है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की ओर से सोमवार को थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं आज शाम को खुदरा महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए जाने हैं। नवंबर महीने में थोक महंगाई दर 4.4 फीसदी, अक्टूबर में 5.28 फीसदी और अगस्त महीने में थोक महंगाई दर 4.62 फीसदी रही थी।

टैक्स क्रेडिट के लिए भरे गए रिटर्न में रिवीजन की इजाजत जल्द

नई दिल्ली, 14 जनवरी (ए)। इंडिया इंक को टैक्सेशन की पिछली व्यवस्था में हासिल टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए दाखिल किए गए गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) रिटर्न में बदलाव करने की इजाजत मिल सकती है। यह छूट उन रिटर्न्स की फाइलिंग से जुड़े मामलों में दी सकती है, जो छोटी-मोटी गैर-तकनीकी दिक्कतों की वजह से खारिज हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल ने तकनीकी दिक्कतों के चलते होनेवाली समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई समिति को इंडस्ट्री को राहत देने का तरीका निकालने पर तेजी से काम करने के लिए कहा है। रिटर्न फाइल करने में हुई गलतियों के चलते हजारों करोड़ रुपये के टैक्स क्रेडिट क्लेम खारिज कर दिए गए थे। इसके चलते बहुत सी कंपनियां अदालत चली गई थीं।

रिटर्न में बदलाव करने की सहूलियत मिलने से उन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें छोटे-मोटे नॉन टेक्निकल एरर के चलते टैक्स क्रेडिट से हाथ धोना पड़ गया था। मामले के जानकार सरकारी सूत्र ने ईटी से कहा, काउंसिल ने गैर तकनीकीगलतियों वाले रिटर्न्स में बदलाव करने की इजाजत दी है।

सरकार को लगता है कि जिन मामलों में गलती साफ दिख रही है या जिनमें हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किए हैं, उनका सेटलमेंट कर दिया जाना चाहिए। जिन मामलों में हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है या जिनमें रकम गलत भरी गई है या जिन मामलों को संबंधित क्षेत्र के कमिश्नर ने रेफर किया था, उन सभी मामलों के निपटारे के लिए शिकायत निपटारा समिति स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगी।

जीएसटी लॉ में TRANv या TRANw से संबंधित मामलों में अपील का प्रोविजन नहीं है इसलिए बहुत से टैक्सपेयर्स ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की और इस व्यू के साथ अनुकूल आदेश हासिल किए कि उनसे हुई गलती दूर करने देने की इजाजत देने पर सरकार को विचार करना चाहिए। कई टैक्सपेयर्स ने उनमें संशोधन की इजाजत के लिए सरकार और जीएसटी काउंसिल के पास अपने प्रतिनिधि भेजे थे। नेशनल इनडायरेक्ट टैक्सेज लीडर प्रतीक जैन कहते हैं, बहुत सी कंपनियां अनजाने में हुई गलतियों के चलते TRANv के तहत क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाईं। जीएसटी काउंसिल की पहल से कंपनियों को अदालत का रुख किए बिना अतिरिक्त रकम क्लेम करने में मदद मिलेगी। कुछ कंपनियां पहले ही अदालत चली गई हैं। त्रस्ज्ञ से पहली वाली व्यवस्था में जमा हुए टैक्स क्रेडिट को जीएसटी वाले नए सिस्टम में हासिल करने के लिए कारोबारियों को TRANv फाइल करना पड़ा था। सरकार ने 27 दिसंबर 2017 तक TRANv में बदलाव करने की इजाजत दी थी। बहुत से कारोबारी रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाए थे जिसके चलते क्रेडिट के तौर पर हासिल होनेवाली मोटी रकम से हाथ धोना पड़ गया था। कुछ कारोबारियों का क्लेम तो टाइप की गलतियों के चलते खारिज हो गया था।

फंसे कर्जों पर बढ़िया प्रदर्शन करने वाले बैंकों को मिलेगा आरबीआई से तोहफा

नई दिल्ली, 14 जनवरी (ए)। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच जल्द ही स्ट्रेस्ड बैंकों के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क में ढील पर सहमति बन सकती है। यह राहत उन बैंकों को ही मिलेगी, जिन्होंने बैड लोन की समस्या को हल करने में अच्छी पहल की है। अभी 11 सरकारी और एक प्राइवेट बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के तहत हैं। जिन बैंकों को पीसीए में डाला जाता है, उनके जोखिम वाले कर्ज देने और ब्रांच की संख्या बढ़ाने पर रोक लग जाती है। ऐसे बैंकों पर दूसरी पाबंदियां भी लगाई जाती हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, हम सारे बैंकों को पीसीए से बाहर करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ उन बैंकों के लिए यह राहत चाहते हैं, जिन्हें इससे रिकवरी में मदद मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि कुछ बैंक तो फरवरी में ही पीसीए से बाहर आ सकते हैं। सरकार को लगता है कि हाल में सरकारी बैंकों को फंड दिए जाने के बाद कैपिटलाइजेशन को लेकर उनकी स्थिति सुधरी है। इसलिए उन्हें पीसीए से बाहर करने का आधार बनता है। अधिकारी ने कहा, हमने सरकारी बैंकों की फंडिंग की समस्या दूर कर दी है। इन बैंकों ने न सिर्फ लोन रिकवरी में प्रगति की है बल्कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का रिस्क भी काफी घटाया है। पिछले महीने सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को और 41 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इससे वित्त वर्ष 2019 में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को सरकार से मिलने वाली कुल रकम 65 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपए हो गई।

जेट में निवेश के लिए एतिहाद की शर्त, गोयल छोड़ें कंट्रोल

मुंबई, 14 जनवरी (ए)। जेट एयरवेज, उसे कर्ज देने वाले बैंकों और उसकी पार्टनर एतिहाद एयरवेज के बीच इस एविएशन कंपनी को बचाने की बातचीत रुकी हुई है क्योंकि खाड़ी देश की एयरलाइन ने जेट में और निवेश के लिए कई शर्तें रख दी हैं। खासतौर पर वह जेट एयरवेज की खातिर और कर्ज देने के लिए अपने हिस्से के इसके शेयर गिरवी रखने को तैयार नहीं है। इस मामले से वाकिफ दो सूत्रों ने यह जानकारी दी है। एतिहाद के पास अभी जेट के 24 पर्सेंट शेयर हैं। जेट ने उससे और निवेश करने को कहा है। उधर, बैंकों ने कहा है कि जब तक जेट को उसके मौजूदा शेयरहोल्डर्स से अतिरिक्त फंड नहीं मिलता, तब तक वे कंपनी को और कर्ज नहीं देंगे। एतिहाद ने कंपनी में निवेश के लिए चेयरमैन नरेश गोयल की हिस्सेदारी 51 पर्सेंट से घटाकर 22 पर्सेंट करने की शर्त भी रखी है। उसने कहा है कि गोयल के हाथ से फैसले करने का अधिकार छीना जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जेट में जितना पैसा एतिहाद लगाएगी, भारतीय बैंक कंपनी को उससे दोगुना कर्ज देने को तैयार हैं।

यह पता नहीं चला है कि एचएसबीसी दुबई और मशरेक जैसे जेट के विदेशी लेंडर्स उसे और कर्ज देने को तैयार हैं या नहीं। इन दोनों बैंकों को जेट को दिए गए लोन पर एतिहाद की गारंटी मिली हुई है। इस खबर को लेकर पूछे गए सवालों पर एतिहाद के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी अफवाहों पर कॉमेंट नहीं करती। जेट एयरवेज ने भी यही जवाब दिया। एतिहाद की शर्तों की वजह से जेट को बचाने में देरी हो सकती है। मार्केट शेयर के लिहाज से देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन 25 साल के अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कंपनी के पास कैश नहीं है, उस पर काफी कर्ज है और वह घाटे में चल रही है। जेट दिसंबर में लोन पेमेंट पर डिफॉल्ट कर चुकी है। पिछले साल वह एंप्लॉयीज को लगातार देरी से सैलरी देती रही। उसके कई हवाई जहाज जमीन पर खड़े हैं। उसने इस संकट से उबरने के लिए छंटनी की है और फ्लाइट्स की संख्या घटाई है। जेट निवेश के लिए एतिहाद को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे निवेशकों की तरह उसने भी गोयल के सामने कंट्रोलिंग स्टेक और मैनेजमेंट कंट्रोल छोड़ने की शर्त रखी है। हालांकि, इस सूरत में एतिहाद को किसी भारतीय पार्टनर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि विदेशी एयरलाइन कंपनियों को किसी भारतीय कंपनी को मैनेज करने का अधिकार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि गोयल ने एतिहाद की शर्त पर हामी नहीं भरी है। वह कंपनी को बचाने के लिए टाटा ग्रुप से भी बात कर रहे थे, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है।

20,000 रुपए तक के 3 ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फोन लाएगी सैमसंग

नई दिल्ली, 14 जनवरी (ए)। सैमसंग तीन नए हैंडसेट लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनकी बिक्री सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिये की जाएगी। इनकी कीमत 10,000 रुपये से कम से शुरू होगी और 20,000 रुपये तक जाएगी। सैमसंग ने चीन की शाओमी से नंबर वन का ताज छीनने के लिए ई-कॉमर्स के जरिये बिक्री बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी के नए एम सीरीज के स्मार्टफोन का टारगेट मिलेनियल होंगे, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से फोन खरीदना पसंद करते हैं। इसी सेगमेंट की वजह से शाओमी को सैमसंग पर बढ़त बनाने में मदद मिली। सैमसंग इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट असीम वारसी ने बताया, च्भारत के मिलेनियल कंज्यूमर को ध्यान में रखकर नई सीरीज को डिजाइन किया गया है। हम ऑनलाइन बिजनेस के डबल होने की उम्मीद कर रहे हैं।ज उन्होंने बताया कि सैमसंग पहले की तरफ ऑफलाइन चैनल पर फोकस बनाए रखेगी, जहां वह खुद को स्थापित कर चुकी है। वारसी ने कहा, यह कोई बदलाव नहीं है। हम ग्राहकों पर और अधिक फोकस कर रहे हैं। हाल में देश में ई-कॉमर्स एफडीआई के रूल्स सख्त करने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वारसी ने कहा, हम नई पॉलिसी के मुताबिक बिजनेस करेंगे। नई पॉलिसी में ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बराबरी का मौका देने की पहल की गई है।

शाओमी पिछले एक साल से देश की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी बनी हुई है। पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच इसका मार्केट शेयर 27.3 पर्सेंट रहा, जबकि सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी उस वक्त 22.6 पर्सेंट थी। आईडीसी के मुताबिक, शाओमी की ऑनलाइन सेगमेंट में हिस्सेदारी 50 पर्सेंट के करीब है। इसके साथ वह फिजिकल स्टोर्स के जरिये भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में तेजी से विस्तार कर रही है।

सैमसंग को क्या नई सीरीज के फोन से मार्केट शेयर बढ़ाने में सफलता मिलेगी, इस सवाल के जवाब में वारसी ने कहा, कई चीजों और बिजनेस एफर्ट का नतीजा मार्केट शेयर होता है। उन्होंने बताया कि जीएफके के डेटा के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर 2018 क्वॉर्टर में वैल्यू के लिहाज से सैमसंग का मार्केट शेयर 40 पर्सेंट रहा। पिछले साल की तुलना में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, काउंटरप्वाइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर (डिवाइसेज एंड ईकोसिस्टम्स) नील शाह ने कहा, सैमसंग के लिए ऑनलाइन सेगमेंट में शाओमी की पकड़ कमजोर करना आसान नहीं होगा।

वायदा सोना भाव 167 रुपये चढ़ा

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (ए)। वैश्विक बाजारों में अच्छे माहौल का असर घरेलू स्तर पर भी दिखा और सोमवार को सटोरियों के अपने सौदे बढ़ाए जाने से सोना वायदा भाव 167 रुपये चढ़ गया। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी के सौदों के लिए सोना वायदा भाव 167 रुपये यानी 0.52 प्रतिशत चढ़कर 32,095 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। इसके लिए 12,675 लॉट का कारोबार हुआ। इसी प्रकार अप्रैल डिलीवरी के सौदों के लिए 6,265 लॉट के कारोबार में यह भाव 182 रुपये यानी 0.57 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 32,220 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना भाव 0.11 प्रतिशत बढ़कर 1,228 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया।

इंटरनेट पर जल्द बंद हो जाएंगे स्पैम और घटिया ऐड

नई दिल्ली, 14 जनवरी (ए)। फेसबुक, गूगल, यूनिलीवर, ग्रुपएम, माइक्रोसॉफ्ट और पब्लिसिस ग्रुप जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऐड स्टेकहोल्डर्स के लिए पॉप ऐड्स, लाइक, कॉमेंट और शेयर के रिक्वेस्ट वाले स्पैम कंटेंट, साउंड वाले ऑटो प्ले विडियो ऐड्स, काउंटडाउन वाले ऐड्स, फुल स्क्रीन स्क्रॉलओवर और सेक्सुअल कंटेंट वाले ऐड गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी। दरअसल ये सभी कंपनियां जिस ऐडवर्टाइजर्स की इंटरनैशनल सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी कोलिशन फॉर बेटर ऐड्स की मेंबर्स हैं, उसने ऐड स्टैंडर्ड्स को तत्काल प्रभाव से रिवाइज कर दिया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऐडवर्टाइजर्स के चीफ एग्जिक्यूटिव स्तेफान लोर्के कहते हैं, ऐसे ऐड्स छ्वक्के स्टैंडर्ड्स और कन्ज्यूमर की स्वीकार्यता के स्तर से नीचे हैं और हो सकता है कि इन्हीं की वजह से कन्ज्यूमर्स ऐड ब्लॉकर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाता है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक इंडिया के प्रवक्ता ने इस बाबत पूछे गए सवालों के जवाब में ईटी को ईमेल भेजी है जिसके मुताबिक, उसकी तरफ से ऐड के बहुत से रिवाइज्ड फिल्टर आ सकते हैं।

स्पोक्सपर्सन ने कहा, हमारे ऐड ऑक्शन में लो क्वॉलिटी एट्रिब्यूट्स वाले इंडिविजुअल ऐड्स का डिस्ट्रीब्यूशन घटेगा या फिर उन्हें नकार दिया जाएगा। यह सभी ऐडवर्टाइजर्स पर लागू होगा लेकिन ऐसी ज्यादातर चीजें मीडिया, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से जुड़े ऐड्स में दिखती हैं इसलिए इनसे जुड़े ऐडवर्टाइजर्स पर ज्यादा असर होगा। उन्होंने कहा कि फेसबुक की मौजूदा ऐडवर्टाइजिंग पॉलिसी में घटिया क्वॉलिटी या डिसरप्टिव कंटेंट वाले ऐड्स पर प्रतिबंध भी शामिल है।

सीबीए ऐड्स स्टैंडर्ड्स ग्लोबल ऑनलाइन ऐड स्पेंडिंग में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले वर्ल्ड मार्केट के फीडबैक के हिसाब से तय करता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स भारत सहित उन सभी देशों में लागू किए जा रहे हैं जहां उसकी सदस्य कंपनियां कारोबार करती हैं। दुनिया के सबसे बड़े मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप ग्रुपएम के मैनेजिंग पार्टनर ब्रैंड सेफ्टी जो बैरन कहते हैं कि सीबीए अपने स्टैंडर्ड्स को दुनिया भर के बाजारों में लागू कराने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा, इसकी वजह एकदम साफ है। जो कन्ज्यूमर के लिए सही है वह ऐडवर्टाइजर के लिए हमेशा सही होगा। ग्रुपएम यूनिलीवर, एडिडास और मार्स का प्रतिनिधित्व करता है।

गूगल क्रोम पर ऐड स्टैंडर्ड्स किस तरह लागू किए जाएंगे इसके बाद गूगल में क्रोम के सीनियर डायरेक्टर-प्रॉडक्ट बेन गैलब्रेथ ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा है, सीबीए की पहल के बाद 9 जुलाई 2019 से क्रोम अपने यूजर प्रॉटेक्शन को विस्तार देगा और हर देश में उन साइट्स पर सभी ऐड्स दिखाना बंद कर देगा जहां डिसरप्टिव ऐड्स आते हैं। उन्होंने कहा कि क्रोम के ऐडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ने इन स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने वाले सभी ऐड की बिक्री बंद कर दी है। ॥रु के स्पोक्सपर्सन ने कहा, हम सीबीए के ग्लोबल मेंबर हैं और हम रिवाइज्ड ऐड स्टैंडर्ड्स को दुनियाभर में लागू करेंगे ताकि हमारे कन्ज्यूमर्स को बेस्ट कंटेंट और ऐड एक्सपीरियंस हासिल हो।

मंथली सब्सक्रिप्शन पर कार लेना फायदे का सौदा

नई दिल्ली, 14 जनवरी (ए)। पुणे की एक मल्टीनैशनल कंपनी (एमएनसी) में काम करने वाले अक्षय छिलाल ने दिवाली से पहले मारुति स्विफ्ट खरीदने का फैसला किया। 28 वर्षीय छिलाल ने बताया, मेरे पास तीन विकल्प थे। पहला, मैं लोन लेकर नई कार खरीदूं और फिर डाउनपेमेंट दूं। दूसरा, अपनी पूरी बचत खर्च करके सेकंड हैंड कार लूं या कार सब्सक्रिप्शन के लिए साइन-अप करूं। छिलाल ने तीसरा विकल्प चुना और इसके लिए सेल्फ ड्राइविंग प्लेटफॉर्म जूमकार, जैप सब्सक्राइब की सर्विस ली। उन्होंने बताया, मैंने फेसबुक पर इसके बारे में पढ़ा था। यह नया कॉन्सेप्ट है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन सभी विकल्पों को देखने के बाद मैंने 6 महीने के लिए कार-सब्सक्रिप्शन लेने का फैसला किया।

जूमकार को रिफंडेबल सिक्यॉरिटी फी के रूप में 2,100 रुपये देने और ?24,638 रुपये की मंथली सब्सक्रिप्शन पर हामी भरने के बाद कंपनी ने छिलाल के घर नई स्विफ्ट की डिलीवरी कर दी। फ्यूल का खर्च छिलाल को ही उठाना होगा जबकि जूमकार दूसरे खर्चों (इंश्योरेंस, रख-रखाव आदि) का जिम्मा उठाएगी। यहां तक कि छिलाल रेंट पर ली गई अपनी कार से पैसे भी कमा सकते हैं।

छिलाल अपनी कार आमतौर पर वीकेंड्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्होंने वीकडेज के लिए कार को जूमकॉरडॉटकॉम पर दर्ज करा दिया था। यह पोर्टल कम दूरी और कम अवधि के लिए भी सेल्फ ड्राइविंग कार रेंट पर देती है। छिलाल ने बताया, नवंबर का महीना काफी शानदार था। इस महीने मैं अपनी कार का काफी कम इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए यह करीब 20 दिन तक रेंट के लिए

अवेलेबल थी जिससे मुझे ?20,500 रुपये की कमाई हुई थी। इस पैसे को उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस में अजस्ट कर लिया गया था। दिसंबर में उन्हें इस कार से 18 हजार रुपये की कमाई हुई थी। हालांकि वह इसके बारे में तुरंत चेतावनी देते हुए कहते हैं, लोगों में यह गलत धारणा है कि वे पोर्टल पर लिस्ट कराकर मंथली सब्सक्रिप्शन से ज्यादा रुपये कमा सकते हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि पोर्टल पर लिस्ट कराने से कमाई की कोई गारंटी नहीं है।

जूमकार वीकेंड्स के साथ एक महीने में 20 दिन के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रहने वाली कार के लिए 10 हजार रुपये कमाई की गारंटी देती है। शुरुआत में छिलाल को डर था कि उनकी कार का रेंट पर लेने वाला शख्स गलत इस्तेमाल कर सकता है या उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, जूमकार ने उनका यह डर दूर कर दिया। उन्होंने बताया, जब कार को कस्टमर ले जाता है और उसे वापस करता है तो उसे कार की कंडीशन के लिए डीटेल चेकलिस्ट पर साइन करना होता है। कार को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने पर जूमकार उसे ठीक कराने की गारंटी देती है।

इन अनुभवों के चलते छिलाल अपनी सब्सक्रिप्शन अवधि को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कार सब्सक्रिप्शन मॉडल तेजी पकड़ता है, तो यह कार को लेकर भारतीय कन्ज्यूमर्स के नजरिए में बड़ा बदलाव होगा। देश की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस तरह के बदलावों का सामना कर रही है, यह उसमें और तेजी लाएगा। इंडस्ट्री के लिए टेक्नॉलजी में बदलाव (इंटरनल कॉम्बशन से इलेक्ट्रिक वीइकल्स), पॉलिसी अपडेट (बीएस-ङ्क्षढ्ढ नॉर्म्स और नए सेफ्टी नॉर्म्स) और ओला-ऊबर जैसे राइड-हेलिंग ऐप कुछ बड़े बदलावों में से एक रहे हैं।